

अम विभाग

आदेश

दिनांक 19 दिसम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/149-86/48100.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी इण्डियन एल्युमिनियम केब्लज लि०, 12/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री टीका राम, मार्फत सी.आई.टी.यू. 2/7, गौपी कालोनी, ओल्ड फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला/मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री टीका राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/191-86/48107.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० के० जी० खोसला कम्प्रेसरस लि०, 18.8 कि० मि० देहली-मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री एच. एन. बतरा पुत्र श्री डी.डी. बतरा, ई-201/1, शाहपुर जेट होज खास नई दिल्ली तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री एच. एन. बतरा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/181-86/48114.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ओसवाल स्टील प्लाट नं० 263, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सूरजित सिंह ग्रहुजा, पुत्र श्री चमन सिंह ग्रहुजा, ई-35, नेहरू, ग्राऊंड एन.आई.टी., फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री सूरजित सिंह ग्रहुजा की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर होकर नौकरी से पुनर्ग्रहण अधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/185-86/48121.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० लखानी रबड उद्योग प्रा० लि०, प्लाट, नं० 235, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री कमलवास चौहान, पुत्र श्री देवकी, संजय कालोनी, सैक्टर-23, ब्लाक-डी नजदीक मुन्दर जनरल स्टोर फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री कमलवास चौहान की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर रह कर नौकरी से पुनर्ग्रहण अधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

अप्र० एस० अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
अम विभाग।